MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 96. Shri Sambhaji Chhatrapati ...*(Interruptions)*...

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 96
TO BE ANSWERED ON JULY 28, 2021

IMPROVEMENTS IN LIVING STANDARD IN CITIES

No. 96. Shri Sambhaji Chhatrapati:

Will the Minister of ***Housing and Urban Affairs*** be pleased to state:

(a) whether Government in consultation with respective State Governments intends to improve the living conditions in the cities which have ranked fairly low in Ease of Living Index-2020;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the major areas in which these cities have scored so low?

ANSWER

THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(SHRI HARDEEP SINGH PURI)

(a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY OF PARTS (a) TO (c) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *96 (6TH POSITION) FOR ANSWER ON 28.7.2021 REGARDING IMPROVEMENTS IN LIVING STANDARD IN CITIES.

(a) & (b): The Ease of Living Index 2020 is a data-driven Assessment Framework aimed at enabling cities assess their performance in addressing challenges faced by their citizens, and benchmarking it against peer cities across the country. The Framework fosters healthy competition between cities, inculcates evidence-based planning, and helps channelize investments and resources in directions most-needed by them. The performance of cities gets assessed through 49 indicators under the 3 pillars of Quality of Life, Economic Ability, and Sustainability. Most importantly, a Citizen Perception Survey, conducted through both offline and online modes across different population strata in the city, is an important component of the Framework. The Framework is open to all Smart Cities and cities over 10,00,000 population as per 2011 census. Ministry actively engages with States and cities in this process right from designing the Framework, data gathering, analysis, dissemination of results and handholding them in their efforts to improve ease of living for their citizens. Various scheme and non-scheme interventions are implemented by Ministry for this purpose. Broadly, a three-level strategy is followed by Government of India in partnership with State Governments and cities as highlighted below:

(i) At the first level, the challenges of poverty alleviation, affordable housing and cleanliness are being addressed through Deen Dayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihood Mission (DAY-NULM), Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban (PMAY-U) and Swachh Bharat Mission-Urban (SBM-U) in all the urban local bodies.

(ii) At the second level, basic infrastructure like water supply and sewerage & septage projects and green parks are in focus. These sectors require economies of scale and hence such projects are being implemented in 500 cities, with 1,00,000 and above population through Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT).

(iii) At the third level, 100 cities are being developed under Smart Cities Mission (SCM) to address the issue of ease of living by evolving new paradigms of urban governance keeping community at the core. Under the Mission, various initiatives have been undertaken to support States/cities to improve ease of living which, inter alia, include development of smart streets, cycling infrastructure, efficient public transport, assured water supply, adequate sanitation facilities, affordable housing, vibrant public spaces, robust IT infrastructure, good governance, health and education.

The findings under the Ease of Living Index 2020 have been captured in the portal - https://eol.smartcities.gov.in/. The portal helps State & city/ other stakeholders identify areas

that need prioritized attention. Further, detailed city fact sheets have been made available to States/ cities, and dissemination workshops have been conducted to enable them make best use of this report. In addition, a Guideline Document titled "Making a City Smart: learnings from the Smart Cities Mission" has been made available to all States & Cities to support their endeavours for smart development in their Cities by replicating the learnings in identified Smart Cities.

(c) As per the results of Ease of Living Index 2020, overall cities have scored an average of 53.51 out of a total of 100 points. Across the pillars, they have scored an aggregate of 51.38 on 'Quality of Life', 13.17 on 'Economic Ability' and 53.63 on 'Sustainability'. Further, within 'Quality of Life', the categories of 'Mobility' and 'Recreation' have received low scores compared to other categories. Under 'Economic Ability', performance of cities in 'Economic Opportunities' component needs focus. Finally, scores under 'Sustainability', 'Green Spaces & Buildings' reflect low performance of cities.

*****

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं0 *96

28 जुलाई, 2021 को उत्तर के लिए

शहरों में जीवन स्तर में सुधार लाया जाना

***96 श्री संभाजी छत्रपती:**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्य-सरकारों से विचार-विमर्श करके जीवन सुगमता सूचकांक-2020 में काफी निचले स्तर पर आने वाले शहरों की जीवन दशाओं में सुधार करने का इरादा रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन शहरों का किन प्रमुख क्षेत्रों में प्रदर्शन खराब रहा है?

<u>उत्तर</u>

<u>आवासन और शहरी कार्य मंत्री</u>

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

शहरों में जीवन स्तर में सुधार लाए जाने के संबंध में दिनांक 28.07.2021 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं0 *96 (छठी स्थिति) के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): जीवन सुगमता सूचकांक 2020 आंकड़ों पर आधारित मूल्यांकन ढांचा है, जिसका उद्देश्य शहरों को अपने नागरिकों के समक्ष आ रही चुनौतियों का समाधान करने में और देश भर के बराबरी वाले शहरों के मुकाबले स्वयं को बेंचमार्किंग करने में सक्षम बनाना है। इस ढांचे से शहरों के मध्य स्वस्थ प्रतियोगिता को प्रोत्साहन मिलता है, साक्ष्य आधारित योजना सृजित होती है और उनके द्वारा सर्वाधिक आवश्यक समझी गई दिशाओं में निवेश और संसाधनों को दिशा देने में सहायता मिलती है। शहरों के निष्पादन का मूल्यांकन जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक सक्षमता और सुस्थिरता संबंधी तीन स्तंभों के अंतर्गत 49 संकेतकों के माध्यम से किया जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से, शहर की आबादी के विभिन्न स्तरों का ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों तरह से कराया गया नागरिक परसेप्शन सर्वेक्षण है, जो ढांचे का महत्वपूर्ण संघटक है। उक्त ढांचा सभी स्मार्ट शहरों और 2011 की जनगणना के अनुसार 10,00,000 से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों के लिए खुला है। मंत्रालय इस प्रक्रिया में ढांचे की डिजाइन तैयार करने से आंकड़े एकत्रित करने, विश्लेषण, परिणामों के प्रसार और अपने नागरिकों की जीवन सुगमता को बेहतर बनाने के लिए उनके प्रयासों में प्रारंभिक सहायता प्रदान करके सक्रिय रूप से राज्यों एवं शहरों के साथ कार्य करता है। मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए विभिन्न योजनागत एवं गैर-योजनागत कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाते हैं। व्यापक तौर पर, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों और शहरों की सहभागिता में एक तीन-स्तरीय कार्यनीति अपनाई जा रही है जो इस प्रकार है:

(i) प्रथम स्तर पर, सभी शहरी स्थानीय निकायों में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और स्वच्छ भारत मिशन शहरी (एसबीएम-यू) के माध्यम से गरीबी उन्मूलन, किफायती आवास और स्वच्छता की चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है।

(ii) दूसरे स्तर पर, जल आपूर्ति और सीवरेज एवं सेप्टेज परियोजनाएं और हरित पार्क जैसी बुनियादी अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन क्षेत्रों हेतु बड़े पैमाने पर किफायत अपेक्षित है और इसलिए इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन 1,00,000 एवं इससे अधिक की आबादी वाले 500 शहरों में अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के माध्यम से किया जा रहा है।

(iii) तीसरे स्तर पर, समुदाय को प्रमुख मानते हुए, शहरी शासन के नए प्रतिमान विकसित करके सुखद जीवन के मुद्दे के समाधान के लिए 100 शहरों का स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के अंतर्गत विकास किया जा रहा है। मिशन के अंतर्गत, सुखद जीवन जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्मार्ट सड़कों, साइकिल संबंधी अवसंरचना, कुशल सार्वजनिक परिवहन, सुनिश्चित जल आपूर्ति, पर्याप्त सफाई सुविधाएं, किफायती आवास, शानदार सार्वजनिक स्थल, सशक्त सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना,

सुशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा का विकास शामिल है, को बेहतर बनाने के लिए राज्यों/शहरों को सहयोग देने हेतु विभिन्न पहल कार्य किए गए हैं।

जीवन सुगमता सूचकांक 2020 के अंतर्गत निष्कर्षों को https://eol.smartcities.gov.in/. पोर्टल में रखा गया है। पोर्टल राज्य एवं शहर/ अन्य हितधारकों को प्रमुख ध्यानाकर्षण वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक है। इसके अतिरिक्त, राज्यों/शहरों को विस्तृत शहर के संबंध में तथ्यात्मक शीट उपलब्ध कराई गई है और उन्हें इस रिपोर्ट का सर्वोत्तम उपयोग करने में सक्षम बनाने हेतु प्रचार संबंधी कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों एवं शहरों को ''मेकिंग ए सिटी स्मार्ट: स्मार्ट सिटीज मिशन से सीख'' नामक दिशा निर्देशी दस्तावेज उपलब्ध कराया गया है, ताकि चिन्हित स्मार्ट शहरों में सीख को पुन: दर्शाकर उनके शहरों में स्मार्ट विकास हेतु किए गए उनके प्रयासों में सहायता मिल सके।

(ग): जीवन सुगमता सूचकांक 2020 के परिणामों के अनुसार, समग्र शहरों ने कुल 100 बिंदुओं में से औसतन 53.51 बिंदु प्राप्त किए हैं। स्तंभों के अनुसार उन्होंने जीवन की गुणवत्ता में 51.38, आर्थिक सक्षमता में 13.17 और सुस्थिरता में 53.63 का योग प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त, जीवन की गुणवत्ता में गतिशीलता और मनोरंजन की श्रेणियों में अन्य श्रेणियों की तुलना में कम उपलब्धी हुई है। 'आर्थिक सक्षमता' के अंतर्गत 'आर्थिक अवसर' के घटक में शहरों के निष्पादन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अंत में, 'सुस्थिरता', 'हरित स्थलों एवं भवन' के अंतर्गत उपलब्धि में शहरों के निष्पादन में कमी परिलक्षित होती है।

****

SHRI SAMBHAJI CHHATRAPATI: Sir, through you, I would like to ask from the hon. Minister that under the AMRUT Scheme, how many cities in Maharashtra have been covered. ...*(Interruptions)*... If so, what is the livability score in the cities and what are the areas of improvement that have been identified? ...*(Interruptions)*...

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, under the AMRUT scheme, which was designed to cover 500 cities throughout the country, all the cities with a population of one lakh or more have been covered and the State-wise details have been provided. I will be happy to provide any further details. Sir, when the AMRUT scheme was started, it covered approximately 60 per cent of the country's urban space and as the hon. Finance Minister mentioned in her Budget Speech, there is a proposal to have a follow up scheme to AMRUT which would cover the remaining parts of the country both for 100 per cent water connections and the sewage and septic treatment and also for the remaining things, particularly, with a focus on Swachh Bharat Mission-II. ...*(Interruptions)*... Through the successor scheme to AMRUT, the rest of the country, 100 per cent, will be covered.

SHRI SAMBHAJI CHHATRAPATI: Sir, recent floods and water clogging in several cities across Kolhapur and Sangli in Maharashtra during Monsoon has exposed the drainage system. Is there a plan to improve upon this system?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, storm water drainage is an important component of the ARMUT scheme. In order to ensure that drains are not clogged during normal times is an effort that every urban local body does make and remains to be made. In so far as any further improvements that may be required either in Kolhapur or in any other city in Maharashtra or for that matter in the entire country, it is something that the urban local bodies will address. We, under AMRUT scheme, provide a total grant of Rs. 50,000 crore over a five year period. ...*(Interruptions)*... The total outlay of Rs. 77,000 crore includes the component of storm water drainage. We believe that the remaining action including the rectification of flooding during the rainy season are actions which the local Government, particularly the urban local bodies will take.

श्री उपसभापति : माननीय सदस्य, वैल में खड़े होकर नारे लगाना, मास्क हटाकर कोविड दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करना, आप खुद तय कीजिए कि यह कैसा है। श्री महेश पोद्दार जी।

श्री महेश पोद्दार : सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि इस देश में स्मार्ट सिटी की करीब 100 योजनाएँ चल रही हैं और यह बहुत अच्छा कदम है। लेकिन, मुझे उनको बताते हुए दुःख होता है कि स्मार्ट सिटीज़ में भी वॉटर ड्रेनेज की समस्या को प्राइयॉरिटी नहीं दी जा रही है। मैं जानता हूँ कि

लोकल स्तर पर ये निर्णय लेने हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी जब केन्द्रीय योजना है, तो महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे आग्रह करना चाहूँगा, इनसे पूछना चाहूँगा कि उसमें वॉटर ड्रेनेज कम्पोनेंट को कम्पलसरी क्यों नहीं किया जा रहा है?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, the Smart City Contest was organized in 2015. Accordingly, 100 smart cities were declared between January, 2016 and 2018. They were based on projects which were identified by the States themselves. It was a system of election and competition. Now, the States have to determine which projects are to taken up. In so far as the Central Government is concerned, we are always willing to support them and if there is an issue which requires to be addressed, every smart city has a Special Purpose Vehicle, it has a special management, they should address this. But, again, if the projects which are to be taken up under the Smart City Projects are projects which the State itself determined at the initial commencement of the plan ...*(Interruptions)*... as I said, I am always happy to sit with my colleague, the hon. Member or for that matter any other hon. Member, to discuss this issue.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Q. NO. 97.